



सामान्य रपिोर्टगि मानक: OECD

प्रलिमिंस के लयि:

सामान्य रपिोर्टगि मानक, आर्थकि सहयोग और वकिस संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD), [सूचना का स्वचालति आदान-प्रदान](#) (Automatic Exchange of Information- AEIO), G20, कर चोरी, [आधार कषरण एवं लाभ हस्तांतरण](#) (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS) ।

मेन्स के लयि:

सामान्य रपिोर्टगि मानक के बढ़ते दायरे की आवश्यकता ।

चर्चा में क्यो?

भारत आर्थकि सहयोग और वकिस संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD) देशों के बीच सूचना के स्वचालति आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information- AEIO) के तहत अचल संपत्तियों जैसे गैर-वत्तितीय परसंपत्तियों को शामिल करने के लयि G20 समूह में सामान्य रपिोर्टगि मानक (Common Reporting Standard- CRS) के दायरे को बढ़ाने पर ज़ोर दे रहा है ।

- भारत में वर्तमान में स्वचालति रूप से सूचना भेजने के लयि 78 अधिकार क्षेत्र और वत्तितीय जानकारी प्राप्त करने हेतु AEIO के साथ 108 अधिकार क्षेत्र है ।
- AEOI अनविासी बैंक खातों की जानकारी को खाताधारक के गृह देश में कर अधिकारियों के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है यह कर चोरी की संभावना को कम करता है ।

सामान्य रपिोर्टगि मानक:

परचिय:

- G20 देशों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए CRS को वकिसति कयिा गया था और 15 जुलाई, 2014 को OECD परिषद द्वारा इसका अनुमोदन कयिा गया था ।
- यह क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अपने वत्तितीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने और वार्षकि आधार पर अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ स्वचालति रूप से उस जानकारी का आदान-प्रदान का प्रावधान करता है ।
- इसमें वत्तितीय खाते की जानकारी साझा करना, रपिोर्टगि कयिे जाने योग्य वत्तितीय संस्थान, कवर कयिे गए खातों और करदाताओं के प्रकार, साथ ही वत्तितीय संस्थानों के लयि एहतयिाती मानक तरीके, इन सभी का इसमें उल्लेख कयिा गया है ।

वर्तमान रूपरेखा:

- वर्तमान में OECD की स्वचालति सूचना आदान-प्रदान (AEOI) रूपरेखा कर चोरी संबंधी जाँच के उद्देश्य से हस्ताकषरकर्त्ता देशों के बीच वत्तितीय खाता वविरण साझा करने में सहायता प्रदान करती है ।
- कर संबंधी सूचनाओं के स्वचालति आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त 2022 में OECD ने करपिटो-एसेट रपिोर्टगि फ्रेमवर्क (CARF) को भी मंजूरी दी जो करपिटो-एसेट्स में लेन-देन संबंधी जानकारी की रपिोर्टगि को एक मानकीकृत स्वरूप प्रदान करता है ।

AEIO के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता:

- AEOI के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि सूचना का उपयोग न केवल कर चोरी की जाँच के लयि कयिा जा सके, बल्कि अन्याय-कर कानून लागू करने के उद्देश्यों हेतु भी कयिा जा सके ।

- जोखिम न केवल वित्तीय संपत्तियों पर है, बल्कि गैर-वित्तीय संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट तथा अन्य संपत्तियों को लेकर भी कर चोरी का जोखिम है, इसलिये **वित्तीय से अन्य गैर-वित्तीय खातों में CRS का वसितार किया जाना आवश्यक है**।
 - OECD की टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान भू-राजनीतिक और ऋण संकट के बीच, विशेष रूप से उन एशियाई देशों द्वारा की गई कर चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह की जाँच किये जाने की आवश्यकता है, जिन्हें वर्ष 2016 में राजस्व में 25 बिलियन यूरो का नुकसान होने का अनुमान है।
 - एक अध्ययन अनुसार, OECD की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि एशिया की 1.2 ट्रिलियन यूरो की वित्तीय संपत्ति का 4% ऑफशोर आयोजित किया गया था, जिससे वर्ष 2016 में इस क्षेत्र को 25 बिलियन यूरो का संभावित वार्षिक राजस्व का नुकसान हुआ।

कर चोरी को प्रबंधित करने के प्रयास:

- वैश्विक प्रयास:
 - [आधार कषरण एवं लाभ हस्तांतरण \(BEPS\)](#)
 - [OECD का समावेशी ढाँचा वक्तव्य](#)
 - [दोहरा कराधान अपवंचन समझौता \(DTAA\)](#)
- भारतीय प्रयास:
 - [भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018](#)
 - [काला धन \(अघोषित वित्तीय आय और संपत्ति\) कर अधिनियम, 2015](#)
 - [धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002](#)

आगे की राह

- वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान का वसितार, कर संग्रह एवं **गैर-कर कानून प्रवर्तन प्रयासों** के लिये महत्वपूर्ण हो सकता है।
- इन पहलों को प्राथमिकता देने की G20 की प्रतिबद्धता से **वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है**, जिससे अंततः सभी को लाभ होगा।
- सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाने और किसी भी संभावित गोपनीयता चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये सीमाओं के पार सहयोगपूर्ण कार्य जारी रखना आवश्यक है। ऐसा करके हम एक नष्टिपक्ष तथा अधिक स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों को लाभान्वित करेगी।

स्रोत: द हिंदू